राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5563/2015

1. रामगोपाल पुत्र श्री परसाराम, जाति जाट, उम्र 23 वर्ष, ग्राम गरासणी, वाया आसोप, तहसील भोपालगढ़ निवासी, जिला जोधपुर।

2. रामदयाल पुत्र श्री मूलाराम, जाति मेघवाल, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम गरासणी, वाया आसोप, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) और जिला कलेक्टर, जोधपुर।

4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, जोधपुर।

5. कार्यक्रम और विकास अधिकारी पंचायत समिति, भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री विकास बिजारनिया।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:- श्री राजदीप सिंह।

माननीय जस्टिस श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

08/02/2024

1. वर्तमान रिट याचिका द्वारा, एक निर्देश की मांग की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को काली सूची से हटाने और उन्हें मनरेगा योजना के तहत साथी के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2009 में पर्यवेक्षी कर्तव्यों के साथ मजदूरों को नियुक्त करने के लिए मनरेगा योजना के संबंध में पंचायत समिति, भोपालगढ़ में साथी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता समर्पण के साथ अपना काम कर रहे थे। निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने के मामले में बिना किसी सूचना के साथियों को हटाने और साथियों के पैनल से नामों को स्वचालित रूप से हटाने के संबंध में प्रतिवादी विभाग द्वारा साथियों के काम और कर्तव्यों के बारे में तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2.2. दिनांक 30.11.2011 के आदेश द्वारा, रोजगार गारंटी योजना आयुक्त ने एक परिपत्र जारी कर इस स्थिति को स्पष्ट किया कि, किसी साथी को हटाने या काली सूची में डालने की आवश्यकता के मामले में, उससे पहले, संबंधित साथी को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में अपना मामला पेश करने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है, और उसके बाद ही साथी को हटाने या काली सूची में डालने के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

2. 3. गरासानी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में भंवर लाल सेंगवा के घर से गांव असावरी के बाहरी इलाके तक बजरी की सड़क बिछाई जा रही है, लेकिन चूंकि यह क्षेत्र अतिक्रमण के

अधीन है, इसलिए अतिक्रमणकारियों द्वारा बजरी की सड़क पर अत्यधिक आपत्ति जताने और झगड़ों में उलझने और मजदूरों को धमकाने के कारण काम नहीं किया जा सकता है, जिससे काम होने से रोका जा सकता है। इस संबंध में, ग्रामीणों ने समय-समय पर सक्षम अधिकारियों को 03.06.2014 और 10.06.2014 दिनांकित अभ्यावेदन दिए हैं, जिसमें बजरी सड़क का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया है।

2.4. प्रतिवादी आयुक्त ई. जी. एस. ने साथियों के संबंध में दिनांक 29.10.2014 का एक परिपत्र जारी किया, जिसमें निर्देश दिए गए कि यदि श्रम भुगतान Rs.30 से कम हैं, तो साथियों को काली सूची में डाला जाना चाहिए। पंचायत समिति भोपालगढ़ के विकास और कार्यक्रम अधिकारी ने दिनांक 29.10.2014 के परिपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ताओं सहित कई साथियों को दिनांक 18.11.2014 के आदेश द्वारा काली सूची में डाल दिया, और जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं को 12.05.2015 पर प्रदान की गई थी।

2.5 दिनांक 18.11.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को निर्देशों का पालन किए बिना, कोई वैध कारण बताए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना काली सूची में डाल दिया गया है।

3.इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

4.उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है।

5. अभिलेख और आरोपों की प्रकृति को देखने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों के आक्षेपित प्रश्न शामिल हैं, उत्तरदाताओं के आरोप के अलावा कि याचिकाकर्ता तथ्यों को छिपाने और दबाने में लिप्त हैं। यह न्यायालय, कम से कम कहने के लिए, पक्षकारों द्वारा दायर हलफनामों और जवाबी-हलफनामे के आधार पर संक्षिप्त कार्यवाही के

माध्यम से ऐसे विवादित तथ्यात्मक आरोपों का फैसला करने के लिए असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र में सुसज्जित नहीं है। इस तरह के आरोपों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, और इसकी उचित सराहना के बाद ही, एक सक्षम अदालत द्वारा निष्कर्ष दिए जा सकते हैं।

6. तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है क्योंकि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। विदा लेने से पहले, मैं जल्दबाजी में यह जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी मामले में याचिकाकर्ता की इस स्तर पर शिकायत मेट के रूप में उनकी सेवा के अनुबंध की समाप्ति नहीं है, बल्कि काली सूची में होने के आवर्ती प्रभाव पर अधिक प्रतीत होती है, जिसके कारण वे अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाओं के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

7. कम से कम कहने के लिए, उस हिसाब से भी, मैं खुद को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करने में असमर्थ हूं, क्योंकि प्रासंगिक समय पर जब उनकी सेवाओं को काम पर रखा गया था, अनुबंध को अधिक से अधिक पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था, और यह कि ऊपरी सीमा होने के कारण, यह पहले से ही रिट याचिका के लंबित होने से बीत चुका है। इसलिए, भोग का कोई मामला नहीं बनता है। इसके अलावा, भविष्य में काली सूची में डालने के संबंध में, यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गंभीर आरोपों पर आधारित है, जिसके लिए विवादित तथ्यों पर खुली सुनवाई की आवश्यकता होती है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इसलिए यह न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

8. बर्खास्त कर दिया।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।